गाद प्रबंधन नीति को जल्द अंतिम रूप दे दे

संजय झा बोले

पटना/ नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने केन्द्र सरकार से सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को जल्द अंतिम रूप देने का अनुरोध किया है।

मंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 'नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2017' का प्रारूप मंतव्य के लिए राज्यों को भेजा गया था, जिस पर बिहार अपना मंतव्य अगस्त 2018 में उपलब्ध करा चुका है। मंत्री गुरुवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 'भारत में डैम सेफ्टी गवर्नेंस हेतु बांध सुरक्षा अधिनियम 2021' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला व मंत्री सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने दक्षिण बिहार में सिंचाई की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए इंद्रपुरी जलाशय योजना जैसे अंतरराज्यीय मुद्दों को सुलझाने में केंद्र से पहल करने का अनुरोध किया। मंत्री ने नेपाल में हाई डैम के निर्माण में केंद्र से पहल का अनुरोध करते हुए कहा कि बिहार हिमालय और नेपाल के डाउनस्ट्रीम में अवस्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य का उत्तरी भूभाग नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ की विभीषिका झेलता है। बिहार में स्थित ज्यादातर बड़े डैम 30 वर्ष से अधिक पुराने हो गये हैं और समय के साथ उनमें सिल्ट जमा होने के कारण उनकी कुल संचयन क्षमता कम हो गई है। इसके पुनर्स्थापन के लिए केंद्र से तकनीकी और वित्तीय सहयोग की अपेक्षा है। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2005 में सरकार बनी और वर्ष 2006 में ही बांध सुरक्षा अधिनियम 2006 को अधिनियमित कर दिया गया। उसके प्रावधानों के आलोक में राज्य बांध सुरक्षा समिति तथा बांध सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया गया था। बिहार में वर्तमान में 27 वृहद डैम और 5 प्रमुख बराज हैं।

नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में बिहार के जल संसाधन त
एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सि

जल शक्ति मंत्री को दिया रबर डैम देखने क

जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा नेकेंद्र
शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बिहार आकर प्रदेश के पहले रब
देखने का निमंत्रण दिया। कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिव
अनुरूप गया में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के पास इस डैम का निम
जा रहा है, जिसमें फल्गू नदी का जल सालोंभर उपलब्ध होगा।